चंबल के घने वनों का विकास

6518. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 1994 में बंजर भूमि विकास कृत्तिक बल गठित करने का कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या यह भी निर्णय लिया गया था कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल के घने वनों के विकास का कार्य इस कृत्तिक बल के माध्यम से शुरू किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या अब तक इस कृत्तिक बल का गठन कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कृत्तिक बल द्वारा वनों के कितने क्षेत्र में बंजर भूमि विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह): (क) से (घ) बंजरभूमि विकास विभाग ने मुरैना जिले के अत्यधिक निम्नीकृत तथा कठिन बीहड़ों के विकास हेतु बंजरभूमि विकास कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया है। भूतपूर्व सैनिकों का यह बल प्रादेशिक सेना निदेशालय की कमान के तहत रहेगा। बल को विभिन्न गतिविधियों, जिनमें भूमि तथा नमी संरक्षण, वृक्षारोपण, और इस तरह से लगाये गये वृक्षों का रख रखाव और संरक्षण शामिल होगा, के जरिए प्रत्येक वृक्ष बीहड़ वाली 390 हैक्टेयर भूमि को विकसित करने का लक्ष्य सौंपा गया है। बंजरभूमि विकास विभाग ने 12 सितंबर, 1994 को बल के गठन हेतु आदेश जारी किये थे। औपचारिकताऐं पूरी होने के पश्चात् बल के गठन को सुगम बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा 13 मार्च, 1995 को आदेश जारी किये गये थे। बल को सही अर्थों में सक्रिय होने में 3 से 6 महीने का समय लगेगा। बल चंबल के बीहड़ों के घन क्षेत्रों में कार्य नहीं करेगा। तथापि, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह मुरैना जिले की अत्यधिक निम्नीकृत और दुर्गम बीहड़ों का विकास करेगा। इस बल के कार्य हेतु स्थल का चयन मध्य प्रदेश सरकार और मुरैना जिला के कलेक्टर के साथ सलाह-मशविरा करके किया गया है।

ग्रामीण निर्धनता पर सुधारों के प्रभाव

6519. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23, फरवरी, 1995 के दैनिक "ऑबजर्वर" में "रिफार्म में ऐड टू रूरल पावर्टी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में वर्तमान आर्थिक सुधारों के नाम पर किए जा रहे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप देश के छोटे किसानों में निर्धनता बढ़ेगी और साथ ही कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी उत्पन्न होगी;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह सच नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगार युवकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वर्ष 1989-90 के दौरान देश के ग्रामीण अंचलों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी तथा मार्च, 1995 तक इनकी अनुमानित संख्या कितनी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) समाचार "विश्व रोजगार, 1995" आई०एल०ओ० रिपोर्ट पर आधारित है। आई०एल०ओ० रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा यह उल्लेख किया गया था कि कृषि में सार्वजनिक निवेश में कमी और कृषि ऋण के प्रावधान से राज्य को पीछे हट जाने, विस्तार सेवाओं की कमी, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप कृषि व्यवसाय को बेहतर प्रोत्साहन जैसे परिवर्तनों से छोटे किसानों की उत्पादन क्षमता कम होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना की तुलना में आठवीं योजना में कृषि के लिए काफी अधिक आवंटन, कृषि ऋण को उन्नतिशील संस्थात्मक बनाने की स्वीकृत नीति और छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए ऐसे ऋण तक बेहतर पहुंच के प्रावधान, कृषि हेतु ऋण के वितरण के 1991-92 के 11507 करोड़ रुपए से बढ़कर 1994-95 में 16700 करोड़ रुपये के प्रत्याशित स्तर तक वृद्धि, आठवीं योजना में विस्तार सेवाओं को और बढ़ाने, लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ की स्थापना, स्थायी कृषि

विकास तथा एक व्यापक ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रम की वजह से कोई कारण नहीं है कि छोटे किसानों में गरीबी का स्तर अथवा कृषि में बेरोजगार बढ़ेगा।

(घ) और (ङ) बेरोजगारी 1989-90 के अन्त में 13.85 मिलियन से बढ़कर 1993-94 के अन्त में 18.87 मिलियन हो गई है और इसके 1994-95 के अन्त में 18.69 मिलियन रह जाने का अनुमान है। इन अनुमानों के ग्रामीण-शहरी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

Distribution of Loan/Assistance to Farmers Under IRDP

6520. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether timely distribution of loan/assistance to the farmers of the State of Punjab under the Integrated Rural Development Programme was made during the last three years;

(b) if so, the details thereof, State-wise/district-wise/year-wise; and

(c) what effective measures Government propose to take to give loan during the next two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) Small and Marginal farmers apart from Rural Artisan and Agricultural Labourer living below the poverty line constitute target group of IRDP. The performance under IRDP is monitored on state as a whole basis at the centre and therefore, districtwise statistics is not available. However, the State-wise number of families assisted, subsidy and credit mobilised during the last three years is at statement I to III (See below). The State of Punjab has always exceeded the targets under IRDP, which is clear from the Annexures.

(c) A number of steps to improve IRDP have been taken in the recent past. Some of these are abolition of cut-off line for assistance, introduction of Development audit, constitution of High Powered Committee to review IRDP, Extension of Family Credit Plant, revision of norms for IRDP programme infrastructure etc.

Based on the past experience and recommendation of some studies, the practice of allocating physical targets under IRDP has been stopped from the current year i.e. 1995-96. This has been done keeping in view to promote the basic idea of assisting the target group in a manner that they cross the poverty line and authorities do not remain obsessed with the physical/numerical targets at the DRDA level. Therefore, it has been decided that henceforth the performance of the States/UTs would be reviewed on the basis of Credit mobilised.

Statement—I

Physical and Financial performance under Integrated Rural Development Programme for the year 1992-93

(Rs. in lakh)

State/U.T.	Physical Target (Nos.)	Families Assisted (Nos.)	Subsidy Disbursed	Credit mobilised
1	2	3	4	5
1. Andhra Pradesh	138079	179038	4407.97	7248.44
2. Arunachal Pr.	12519	13642	274.95	118.85
3. Assam	37711	40204	1013.01	1681.31
4. Bihar	276337	264252	6496.87	10821.63
5. Goa	2608	2456	30.18	169.13